



VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Rawatbhata Road, Kota -324021
(Estate Office)

Notice Inviting E-Bid

(NIB No. 35 / 2025-26)

Vardhman Mahaveer Open University, Kota invites E-bid under Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 for ARC for hiring of Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled) through service provider on job basis from experienced and Registered bidders under GST fulfilling eligibility criteria (single stage two part bid system) as described in the bid document as appended below :-

S. No.	Name of Work	Estimated Cost Rs.	Bid Security	BID fee Rs.	RISL Processing fees Rs.	Date of Availability of BID	Date of Receiving of Demand Drafts	Date of Opening of Eligibility Bid	Contract Period
1.	“ARC for hiring of Men Power (Skilled/ Semi Skilled/ Unskilled) through service provider on job basis	12.00 Lakh	Rs.24,000/-	1000/-	500/-	13/02 /2026 (1:00PM) To 23/02 /2026 upto 5:00pm	Up to 24/ 02/26 (05:00 P.M.)	25/02 /26 at 11:30 A.M.	One Year

Instructions to Bidders:-

- 1- The detailed scope of work as well as terms and conditions for “ARC for hiring of Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled)” have been given in the BID documents which may be downloaded from <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.rajasthan.gov.in or University website www.vmou.ac.in.
- 2- Bidders can participate in the Tendering Process only Online using <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> website, Bidders should have a valid DSC before bidding.
- 3- The Interested bidders may submit their on-line bids along with separate Demand Draft drawn in favour of “Vardhman Mahaveer Open University” payable at Kota towards the cost of Bid Fee (non-refundable) & Bid Security and RISL Processing Fee (Non-refundable) demand draft shall be in favour of “Managing Director, RISL” payable at Jaipur.
- 4- The above demand drafts must reach physically in the office of OIC Estate, Room no.3, Administrative building, Rawatbhata Road, VMOU Kota 324021 on or before last date as mentioned above failing which bids shall not be considered.
- 5- Bidders, having digital signature certificate (DSC) as per IT Act, 2000 to sign their electronic Bids, shall submit their offer on-line on www.eproc.rajasthan.gov.in with in stipulated time and

date mentioned herein above. Bids shall not be accepted personally. The Bids will be opened on the same date and time before purchase committee in the presence of bidder or their authorized representative who may be present.

- 6- In the event of the specified dates being a holiday, the activities assigned on that date may be carried out on next working day on the same time.
- 7- Price bids of only responsive bidders shall be opened, who have qualified in the Eligibility bids. The date and time of opening the price bids shall be communicated to them through e-procurement system.
- 8- VMOU, Kota is not bound to accept the lowest bid and may reject any bid or any part of the bid without assigning any reason therefore.(RTPP Rule 72)
- 9- Bids received after the prescribed time and date will not be considered.
- 10- Validity: - 90 days from the opening of Eligibility bid/Technical bid.
- 11- In case of any query, the undersigned (Procurement Entity) may be contacted at 0744-2797297 or e-mail at estate@vmou.ac.in .
- 12- Corrigendum if any, will be published on these websites only.

OIC Estate



VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Rawathbhata Road, Kota -324021
(Estate Office)
GSTIN No. 08AAAJV0817C3ZB

NIB No. 35 / 2025-26

खुली बोली (पात्रता बिड) Annexure "E"

उपापन की विषय वस्तु : ARC for hiring of Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled)

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम :-
2. डाक का पता :-
3. फोन/मोबाईल नं. :-
4. ई-मेल :-
5. बैंक का नाम :-
- आई.एफ.एस.सी. कोड :-
- खाता संख्या :-
6. बीड फीस राशि का डी.डी. क्रमांकदिनांकराशि 1000 /-
7. R.I.S.L. प्रोसेसिंग फीस राशि का डी.डी. क्रमांकदिनांक राशि 500 /-
8. बिड सिक्यूरिटी राशि का डी.डी. क्रमांक..... दिनांक राशि रु.24,000 /-
9. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ अपलोड करनी होगी :-

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

10. समस्त पंजीकरण संविदा अवधि अर्थात् कार्यादेशित अवधि तक valid/विधिमाम्य होने चाहिए। validity न होने पर मान्य नहीं होंगे। कूटरचित पाये जाने पर RTPP 2012 Act, section 11 तथा 46 अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

11. निविदादाता/सेवाप्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाईटी का विगत 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का औसत टर्नओवर राशि रुपये 10 लाख प्रति वर्ष हो। इस हेतु सनदी लेखाकार से वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र **Annexure F** एवं प्रमाणिक दस्तावेज बैलेंस शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expeniture A/c आदि अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
12. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 10 वित्तीय वर्षों (2015-2016 से 2024-25) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थान/परियोजनाए/बोर्ड/समिति आयोग/शिक्षण संस्थान/बैंकों में कम से कम 3 वर्ष सफलतापूर्वक उक्त प्रकार मैनपावर उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है जिस हेतु अनुभव /संतोषजनक सक्षम प्राधिकारी से जारी किया हुआ संलग्न होना अनिवार्य है व जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा जारीकर्ता से की जा सकेगी। जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा :-

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये कार्मिकों की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित समस्त दस्तावेजों/पंजीयन प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों/डिमाण्ड ड्राफ्ट इत्यादि की स्कैन प्रतियां ई-प्रोक्यूरमेन्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। पात्रता विड से संबंधित कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र (डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त) को व्यक्तिगत रूप से/डाक से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
14. फर्म का निविदा जमा की अंतिम दिनांक के 03 वर्ष पूर्व तक ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। **Annexure G**
15. संवेदक/बोलीदाता आवेदक का पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एवं ई-मेल आईडी सहित होना अनिवार्य है।
16. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
17. सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य है।
18. मैं/हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
19. राजस्थान सरकार वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017, जयपुर दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी। साथ ही पालना करने हेतु शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा (**Annexure-H**)। उपलब्ध कार्मिकों को भुगतान की समस्त शर्त उक्त परिपत्र के अनुसार भुगतान अनिवार्य होगा। भुगतान में अनियमितता या प्राप्त शिकायत की पुष्टि पश्चात संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी अधिकतम 10 प्रतिशत लगाई जा सकेगी। लगातार तीन बार भुगतान संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर व पुष्टि में सही पाये जाने पर ठेकेदार को **Debar** किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर पुर्ननिविदा की जा सकेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA



Rawathbhata Road, Kota -324021
(Estate Office)

NIT No. 35 / 2025-26

वित्तीय बोली प्रपत्र

उपापन की विषय वस्तु : ARC for hiring of Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled) through service provider on job basis

1. संवेदक के माध्यम से Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled) की सेवाओं के उपापन के लिये दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट पर अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।

क.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय परिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रुपये में	कुल राशि रुपये प्रति ईकाई
		श्रमिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह प्रति ईकाई रुपये)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रुपये)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ARC for Hiring of Men Power (Skilled, Semiskilled, unskilled)	कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल श्रमिक (कुल 9 श्रमिक)	1. कुशल श्रमिक 8,034 /- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 2. अर्द्धकुशल श्रमिक 7,722 /- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 3. अकुशल श्रमिक 7,410 /- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4 व 6 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 5 एवं 8 में ही बोलीदाता द्वारा ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट पर उपलब्ध BOQ (Price Bid) में समुचित प्रतिष्ठा अंकित की जायेगी।
3. बोलीदाता द्वारा ऑफलाईन प्रस्तुत की गई वित्तीय बोली स्वीकृत नहीं की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता को ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं वस्तु एवं सेवाकर राशि (GST) अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

बोलीदाताओं के लिये आवश्यक विनिर्देश व शर्तें

- 1- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
- 2- दरों को BOQ प्रारूप में ऑनलाइन भरा जायेगा।
- 3- निविदा प्रपत्र राशि रूपये 1000 /- और धरोहर राशि रू.24,000 /- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के नाम होगा देय होगा और निविदा प्रक्रिया राशि रूपये 500 /- जो कि MD RISL, Jaipur के नाम देय होगा (अनुसूचित बैंक द्वारा जारी)। समस्त डिमाण्ड ड्राफ्ट एक सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 24/02/2026 को सांय 05:00 बजे तक प्रभारी सम्पदा, कक्ष सं.3, प्रशासनिक भवन, रावतभाटा रोड़, कोटा 324021 के कार्यालय मे जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा नहीं खोली जावेगी।
4. पात्रता निविदा में निम्न दस्तावेजों को अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
 - (a) समस्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रतियाँ।
 - (b) फर्म के समस्त रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जो संविदा अवधि (contract अवधि) तक valid/विधिमान्य हो।
 - (c) पेन कार्ड की प्रति।
 - (d) पात्रता बोली में उल्लेखित अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां। जो संविदा अवधि (contract अवधि) तक valid/विधिमान्य हो।
 - (e) गत 3 वर्षों का सनदी लेखाकार से प्रमाणित वार्षिक टर्न ऑवर की प्रतियाँ। (Annexure F)
 - (f) अनुभव प्रमाण पत्र पात्रता निविदा में वर्णितानुसार
 - (g) Annexure A,B,C,D की हस्ताक्षर युक्त प्रति।
 - (h) किसी भी उपापन संस्था द्वारा फर्म की निविदा जमा की अंतिम दिनांक के 3 वर्ष पूर्व तक ब्लेक लिस्ट घोषित नहीं किया गया है इस आशय का फर्म के लैटरहेड पर हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।(Annexure G)
- 5- पात्रता निविदा मे योग्य पाये जाने पर ही संबंधित बोलीदाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा खोलने की तिथी पृथक से ई-प्रोक पोर्टल के माध्यम से सूचित की जावेगी जो RTPP नियम 63(5) अनुसार होगी।
6. बोलीदाता को विश्वविद्यालय के कोटा स्थित मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रिय केन्द्र (अजमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर) पर भी आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे। उपलब्ध करवाए जाने वाले कार्मिकों की संख्या विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार घटाई अथवा बढ़ायी जा सकेगी।

7. RTPP Act 2012-13 के नियम 73 परिणाम में परिवर्तन का अधिकार के अनुसार:-

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।

(2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यह बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये, मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा रखे जा सकेंगे। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(3) यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाय तो अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गई शर्तों और दरों पर दिय जा सकेंगे और मूल आदेश खुली प्रतियोगी बालियों के आमंत्रण के पश्चात दिये जा सकेंगे। परिदान या पूर्णता कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होगी:-

(क) वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और संकर्म की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और संविदा के अधीन परिकल्पित कार्य के विस्तार को बदले बिना, संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से कोई उपापन संस्था मूल संकर्म आदेश में यथा उपबन्धित वैयक्तिक मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा का उपापन निम्नानुसार कर सकेगी:-

(i) कि उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, पुनरीक्षित अपेक्षाओं के लिए संक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की मात्राके कारण, जहां कही आवश्यक हो, उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व और पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी अभिप्राप्त करेगी।

(ii) कि इस प्रकार उपाप्त अतिरिक्त मात्राएं निष्पादित किये जाने वाले कार्य का भाग होगी।

(iii) कि मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी दशा में नहीं बढ़ाई जाएगी।

8. टी.डी.एस. नियमानुसार प्रतिमाह के बिल से काटा जावेगा।

9. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

10. यदि इस निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट www.v mou.ac.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in अपलोड/जारी किया जावेगा।

11. अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अनुरूप होगी।
12. एक बार कार्मिक लगाने के बाद बिना प्रभारी की अनुमति के कार्मिक बदला नहीं जावेगा।
13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- 14- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ ऑन-लाईन प्रस्तुत की जायेगी।**
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिक को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
18. दर संविदा अवधि में श्रम कानूनोन्तर्गत श्रेणीगत न्यूनतम पारिश्रमिक/मजदूरी भुगतान संविदा दाता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा श्रम कानूनोन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा सकेगा तथा इस हेतु श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम दरों में अभीवृद्धि किये जाने पर निविदित दरों के अनुपातिक दर अभीवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
19. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
20. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

21. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- 22-** श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
23. **Minimum Wages, EPF & ESI** की दर राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवर्तनशील होगी। यदि कॉलम न. 5 में सफल संवेदक द्वारा कॉलम न. 4 से अधिक दर भरी जाती है तथा भविष्य में कॉलम न.4 में अंकित न्यूनतम मजदूरी दरों में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है तो कॉलम न.5 में अंकित दर में न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा तक ही वृद्धि की जावेगी।
24. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी जिसमें वृद्धि **RTPP Act 2012** एवं **2013** नियमों के नियम 29 अंतर्गत 03 माह तक वृद्धि की जा सकेगी।
25. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा उत्तरदायी नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
26. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
27. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को

अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को **Debar** कराने की कार्यवाही की जायेगी।

29. संवेदक को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
30. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर आर. टी.जी.एस. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
31. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
32. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडऱ (Sub-Let) पर नहीं देगा।
33. यदि किसी बोलीदाता पर कोई वैधानिक अधिनियम लागू नहीं होता है और वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसकी बोली नियमानुसार मान्य की जा सकेगी।
34. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (**Agreement and Performance Security**):
 - (अ) बोली आमन्त्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस. आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 - (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
 - (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
35. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (**Forfeiture of Work Performance Security Deposit**) : कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (**Forfeiture**) किया जा सकेगा :-
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
 - (घ) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध समाप्ति पश्चात 06 माह पश्चात लौटाई जा सकेगी।

36. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
37. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क किया जा सकता है।
38. न्यूनतम बोली दाता का निर्धारण Total Amount के कॉलम में प्राप्त दर से ही किया जायेगा।
39. सफल निविदाओं में समान Total Amount प्राप्त होने पर RTPP, 2013 अन्तर्गत L-1 निविदादाता एक से अधिक होने पर उपापन को समान रूप से वितरित कर कार्य आदेश दिया जा सकेगा अर्थात् कार्यादेश को बराबर बाँटा जा सकेगा जो अवधि, संख्या इत्यादि के आधार पर हो सकता है।
40. RTPP नियम 2013 के नियम 47 के अन्तर्गत निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निविदा प्रपत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित में प्रभारी अधिकारी सम्पदा प्रकोष्ठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
41. संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

क्र.सं	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6

42. विश्वविद्यालय के मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय केन्द्रों पर उपलब्ध करवाये जाने वाले Men Power (Skilled/Semi Skilled/Unskilled) की अनुमानित संख्या।

S.No.	Name of Department	Tentative requirement
1.	Head Quarter at kota	05
2-	Regional Centre Jaipur	03
3.	Regional Centre Udaipur	01
Total		09

43. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता को खातों में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
44. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

प्रभारी अधिकारी (सम्पदा)

मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्तक्षार
(निविदादाता)

दिनांक :

नाम :-

Annexure F

वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.....
का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत चार वर्ष की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाखों में)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Annexure G

घोषणा—पत्र

E-bid की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में E-bid में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/ प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा “अधिनियम” की धारा 46 एवं “नियम” 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से निविदा जमा की अंतिम दिनांक के 3 वर्ष पूर्व तक अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा खुली बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

शपथ-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म द्वारा राजस्थान सरकार वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017, जयपुर दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- a. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
 - b. Have controlling partners/shareholders in common; or
- c. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- d. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
- e. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- f. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- g. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
- 1. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to **VMOU Kota** for procurement of “ARC for hiring of Computer Machines along with trained personnel.” in response to their Notice Inviting Bids No 35 /2025-2026 dated 09/02 /2026. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

- 1- I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
- 2- I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
- 3- I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
- 4- I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
- 5- I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is **Hon'ble Vice-Chancellor, VMOU, Kota.**

The designation and the address of the Second Appellate Authority is **Additional Chief Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur.**

1- Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2- The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3- If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4- Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a. Determination of need of procurement;
- b. Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c. The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d. Cancellation of a procurement process;
- e. Applicability of the provisions of confidentiality.

5- Form of Appeal

- a. An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6- Fee for Filing Appeal

- a. Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- b. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- a- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b- On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c- After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d- The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Form No. 1
[See Rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- i. Name of the appellant:
- ii. Official address, if any:
- iii. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- i.
- ii.
- iii.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provision of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D:

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address: